372

[SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHY] Stopped immediately, and all the works have to be given to this Workshop staff only.

Sir, I would request the Ministry of Railways to answer the following questions : (1) What action is being taken by the Railway Administration regarding modernisation of the Engineering Work shop at Arkonam ? Even though Rs. 4.8 crores were sanctioned, only a meagre amount of Rs. 1 lakh was allotted this year. (2) Why is the delay in the recruitment of Class-TV employees in the EMS? Only 342 Class-IV employees are available against the sanctioned strength of 610. (3) What can be done to see that the carpenter, wood-work, tinker and painter shops are not closed down ? (4) What is the remedial action taken to promote the employees who are on the verge of retirement ? (5) Who has stopped appointments on compassionate grounds in the Workshop ? Since the families of the deceased employees are settled at Arkonam itself? (6) What steps can be taken for the appointment of people on compassionate grounds ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Saqhy, now please try to conclude.

SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHY: (7) How can the production control organisation function with limited staff when there are a number of vacancies in the categories of Chargeman B, Mis-try, Progressman and Junior Planner? (8) What is the action taken by the Ministry of Railways to implement restructuring of various posts which was

, already accepted by the JCM?

Sir, I request the Ministry of Railways and the Ministry of Industry to look into this sensitive subject and take all possible remedial action in the matter immediately. Otherwise, Sir, there is the possibility of closing down this 110-years old Engineering Workshop at Arkonam. Thousands of employees are working there. There is no other factory around that area. So, this factory has to be protected; The closing down of the factory with *mala fide* intentions has to be stopped in the interest of the people living in that area. Thank you, Sir.

SHRI MISA R. GANE3AN (Tamil Nadu) : Sir, I associate myself with this Special Mention.

Demand to Hand-Over S.Y.L. Canal work to Border Roads Organisation

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): उपसभाघ्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको पीठासीन अधिकःरियों की अमात में शामिल होने के लिये बधाई देना चाहती हूं।

श्री जगर्बःश प्रसाद माथुरः (उत्तर प्रदेश यह भी अलग जमात है ? हम समझे कि पैनल है।

श्रीसती सुबमा स्वराज : एक अलग परि-वार है श्रीर कल ही आपका मनोनयन हुआ है।

उपसमाम्यक्ष (श्री सैयव सिक्से रखी) : बडे हाउस की छोटी जमात है।

श्रीमती सुखमा स्वराज : महोदय, मुझे आपकी सदारत में बोलने का मौका मिल रहा है, यह मेरे लिये खुशी की बात है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं इस महान सदन का ध्यान एक आवश्यक विषय की श्रोर दिलाना चाहती हूं। आप जानते हैं कि सतलुज-यमुना लिक नहर का निर्माण हमारे प्रदेश के निवासियों के लिये एक बहुत ही महत्व का मसला है। सतलुज-यमुना लिंक नहर हरियाणा की प्राण रेखा, लाइफ लाइन के नाम से युकारी जाती है। हरियाणा की असिचित भूमि बर्षों से इस नहर के जरिये आने वामे पानी का बेताबी से इंतजार कर रही हैं। किन्तु हरियाणा मे किसानों को आज तक केन्द्र सरकार की आरेर से सिवाय खोखले वायदे और कोरे आश्यासनों के इस विषय पर कुछ नहीं मिला भीर पिछले महीने की 27 तारीख को इसी सदन में जल संसाधन मंत्री विद्या चरण गुक्ल जी हारा दिये गये एक अझ्न के जवाब ने तो हम लोगों की उम्मीदों पर बिल्कूल पानी फेर कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है बह इस नहूर के निर्माण के लिए कहा से खर्चा साएगी । जो हमारे हिस्से की नहर बनी है, जो वर्षों पहले पूरी हो गई, उस पर करोड़ों क्यया खर्च हुआ फिर आज तो उसकी निर्माण लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब सरकार की नीयत और पंजाब सरकार का पैसा, यह दोनों मिल कर के एक बहुत बड़ा प्रश्न विह्न इस नहर के निर्माण के सामने लगा रहे है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस नहर का निर्माण पूरा न **होने के कारण हरियाणा** के किसानों में बहुत उत्तेजना है। हजारों हैक्टेयर भूमि हमारे प्रदेश में अभी **जसिषित** पड़ी है इस पानी के अभाव में, साबों दन कृषि उपज से देश वंचित हो रहा है झौर करोड़ों रुपयों का धाटा हरियाणा सरकार को उठाना पड़ रहा है लेकिन इन सब सथ्यों की केन्द्रीय सरकार अनदेखी कर रही हैं। वर्षांव अपनी ओर से किसी एजेंसी को, सीमा सड़क संगठन जैसी एजेंसी को इस नहर का निर्माण कार्य सौंपने के, पंजाब सरकार को इस झायें को सौंप कर के इस के निर्माण कार्य में अड़ंगा डाल रही हैं। मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के माध्यम से जल संसाधन मंती जी अनुरोध करना चाहती हुं कि इस मसने की नजाकत को, पहुत्व को समझें और वन्द्रवेवर जी की सरकार के समय लिये गये लिण्य के अनुसार इस नहर का निर्माण कार्य सीमा सडक संगठन को सौंपने का निर्णय लें। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

औं रामजों लाल (इरियाणा) : मैं इस विशेष उल्लेख से एस्सोसियेट करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद नावुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, सुषमा बहन ने तो आपको इस बात पर बधाई दी है कि आप पीठासीन हैं और उनकी जमात में सामिश हैं बैकिन मेरे ग्रौर आपके दरम्यान आज एक डी

दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हरियाणे के हिस्से की नहर मुक़म्मल हो चुकी है लेकिन जो पानी इस नहर के अरिये हरियाणा को मिलना है वह पाकिस्तान को जा रहा है क्योंकि पंजाब के हिस्से की नहर का निर्माण अभी अधर में लटका हुआ है। कई जन-आंदोलन इस मुद्दे पर हरियाणा में हो चुके हैं, कई सरकारी मंचों पर हम अपनी आवाज इसके लिए उठा चुके हैं लेकिन मतीजा वही ढाक के तीन पात।

एक बार चन्द्रशेखर जी की सरकार के समय यह उम्मीद बंधी थी कि इस नहर का निर्माण हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक बैठक की थी श्रीर उस बैठक में उन्होंने एक फैसला लिया था कि इस नहर का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंप देंगे और उसी के माध्यम से इस नहर का निर्माण कार्य करायेंगे। उसके बाद एक बैठक जल संसाधन मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल जी की अध्यक्षता में भी हुई । उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सांसदों को एक साथ बुलाया या और कहा था कि उनके प्रदेश से बाबस्ता मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहेंगे। उस समय हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सांसदों ने इस बात को एक स्वर से कहा था कि उम्स सतसुज-यमुना लिक नहुर के निर्माण के बारे में चिंतित हैं। उस समय श्री विद्या चरण शुक्ल जी से भी इस नहर के निर्माण कार्य को सीमा सडक संगठन को सौंपने की बात कही थी। लेकिन आज से चार विन पहले इस सदन में उनके जवाब को सुन कर मुझ्ने इस बात की हैरानी हुई कि "इसका निर्मात कार्य सीमा सडक संगठन को नहीं सौंपा गया बल्कि पंजाब सरकार को इस निर्माण कार्यको पूरा करने के जिए हम कह रहे हैं और मैंने खुद एक पत्र इस ब/रे में मुख्य मंत्री को इस बारे में लिखा है।" महोदय, मैं साफ कहना चाहती हूं कि सदम में इस तरह का उत्तर इस नहर के निर्माण कार्य को खटाई में डालने की साजिश है। केन्द्र सरकार जनती है कि पंजाब सरकार के पास तो अपना

Difficulties for Indians In getting Visa tot visit U.K.